जाए । जिनके साथ बलात्कार हुआ है उनके परिवार को पांच-पांच लाख रुपये और एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए । धन्यवाद ।

Re. Infrastructure Equalisation plan in the north-eastern region at par with national average by 2000 AD.

SHRI W. ANGOU SINGH (Manipur): Madam, through this Zero Hour submission, I would like to raise an issue which is agitating the minds of the people of North-East, particularly Manipur. The issue that I am going to raise is with regard to infrastructure equalisation plan in the North-Eastern Region at par with the national average by 2000 A.D. Madam, the country is on the threshold of the 21st century and the strategies for the 9th Five Year Plan will be critical. Madam, we are going to celebrate the 50 years of our Independence. But, there is still a wide gap of infrastructure availability in the North-East as compared to the whole country. Being a citizen of the country, I would not only like to focus on the data of road and railway networks, *per capita* power consumption, telecom services and other essential services but also ask why the States of the North-East, particularly, like Manipur continue to be rooted in backwardness.

Madam, in this respect, I would like to submit the present position of the State of Manipur. The State of Manipur is lagging behind the nation by 21% in respect of the infrastructure development. This is as per the index of the relative development prepared by the CMIE in 1991-92. Manipur has no railway line and water way. It has low road density of 13.30 kms. per 1,000 sq. kms. as against the national average of 62.82 kms. The State's *per capita* energy consumption is only 140.4 K.W. as against the national average of 330.6 K.W. The State has no industrial zone. The State Employment Exchanges have registered above 2.77 lakhs of names as on 30-04-1996, but according to the 1991 census, the State's population is 18.37 lakhs only. Over and above, fund released to this State during the First Five Year Plan was only Rs. 1.55 crores; during the Second Five Year Plan Rs. 6.25 crores during the Third Five Year Plan, Rs. 12.95 crores during the Fourth Five Year Plan, Rs. 30.25 crores during the Fifth Five Year Plan, Rs. 92.86 crores during the Sixth Five year Plan, Rs. 240 crores during the Seventh Five Year Plan, Rs. 430 crores and during the Eighth Five Year Plan, Rs. 979 crores were released. These are some of the main causes for the present grave situation in the State.

Hence, my suggestion is, priority of the Central Government in the Ninth Five Year Plan must, therefore, be to develop the infrastructure in the Norty-Eastern Region on a par with the national average by 2000 A.D. This plan must be coupled with a definite strategy for activating both the public sector and the private sector investment which can catalyse economic, industrial and commeicial activity. The Central Government's economic liberalisation programme must exhibit a bias in favour of disadvantaged and geographically remote States of the North-Eastern Region, especially Manipur.

Madam, taking advantage of Zero Hour, I now raise this issue, in this House, for attracting the attention of the hon. Prime Minister and his Cabinet colleagues in order to prepare an infrastructure equalisation plan in the Ninth Five Year Plan, specially for the North-Eastern States, so that the sentiments and discontant among the people of the North-East can be controlled and to strengthening the country united and integrated.

Thanking You.

Re. Plight of potato growers in West Bengal

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिम बंगाल): धन्यवाद महोदय । मैं आप के माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करने जा रहा हूं । महोदय, पश्चिम बंगाल और देश के

अन्य भागों में इस साल इतना ज्यादा आलू का फलन हुआ है कि वह आलू उत्पादन किसानों के लिए एक बदनसीबी का कारण बन गया है । उनके पास उसे रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है महोदया,हमारे देश में एक तरफ तो लोग भूख के कारण मर जाते हैं और दूसरी तरफ जब ज्यादा फलन होता है तो उसे बाजारों में और गोदामों में रखने की उपयुक्त जगह नहीं मिल पाती । मैडम, अभी पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी देकर कुछ आलू रखा गया है ।

अभी उस आलू के भी बाहर निकालने का वक्त आ गया है । और जो नया फलन हुआ है वह सब इस तरह से सड़ रहा है । इसके पीछे कई कारण हैं । एक कारण तो यह है मैडम कि 1950 से मेरे जन्मसे पहले बंगाल में आलू का जो एक सीड फार्म था वह वायरस अफ्केटेड हुआ था । उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी कि बंगाल का आलू विदेश में या देश के अन्य राज्यों में नहीं जाएगा । उसके बाद जो बिजनबाड़ी सीड फार्म था उसे बन्द कर दिया गया । फिर यहां नैनीताल से,पंतनगर से और हिमाचल से सीड वहां ले जाया गया । उसके बाद इतनी साल में नये तरीके से गये सीड से ज्यादा फलन हो ऐसे आलू की तैयारी की गयी । अब वह सीड दूसरी जगह भी जाता है । साउथ इंडिया में जा रहा है । आलू भी जा रहा है । बंगलादेश हुकूमत आलू खरीदना चाहती है । रेडी है । लेकिन यह दिखाया जाता है कि 1959 का आर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आलू में वायरस हुआ था इसलिए वह आलू आप विदेश में नहीं भेज सकते हैं । जबकि साउथ में हमारा बंगाल का आलू जाकर वहां से श्रीलंका तक जा रहा है स्मगलिंग हो रही है बंगलादेश में । बंगला देश में जो स्मगलिंग रैकेट है आज वह दिल्ली में बहुत हावी है । कानून वह नहीं जा सकता है वायरस की वजह से, लेकिन रोज ही आप देखें सड़क के किनारे में बार्डर एरियाज में, (व्यवधान) वह वहां अनआफिशियली जा रहा है । यहां कृषि मंत्री जी मौजूद हैं । कामर्स मिनिस्टर से बात करें । उस आर्डर को चेंज करें । सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई राय है तो उसको बदलें । वह जमाना बदल गया है । वह आलू बदल गया है । उस स्पेसी का आलू नहीं है। दूसरे किस्म का आलू बनाया जा रहा है। लेकिन बदनसीबी हमारे मुल्क में यह है कि वह आर्डर अभी चल रहा है। बंगला देश की हुकूमत एक तरफ आलू खरीदना चाहती है, इम्पोर्ट के लिए तैयार है लेकिन हमारे यहां रेस्टिक्शन है सेंट्रल गर्वनमेंट की। क्यों है? जो खाएगा, जो लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। उनको समझ में आ गया है कि यह वायरस वाला आलू नहीं है। लेकिन हमारे दिल्ली सरकार को अभी तक समझ में नहीं आया है कि जो वायरस वाला मामला था उस रेस्ट्रक्शन को हटा देना चाहिए दूसरी तरफ आज भी देश में- यह सिर्फ बंगाल में नहीं है यू.पी. में भी कई जगह पर है कि आलू का किसानों को 50 पैसे किलो नहीं मिल रहा है और शहरों में आप आइए अभी भी 3-4 रुपए किलो या 10 रुपए किलो मद्रास और बम्बई में है । रेल मंत्रालय से आप बात कीजिए कृषि मंत्री जी। जब डिस्ट्रेस सेल होती है उसमें किसानों को बचाने के लिए आप कुछ न कुछ अलग से देते हैं, कुछ इन्सेटिव देते हैं । किस तरह से आप किसानों की मदद करेंगे इस बारे में सोचें । बंगाल की हुकुमत से बात कीजिए । बंगाल की हुकुमत आपसे बात कर रही है। जरूरत पड़े तो स्पेशल रेल चलाइए " आलू स्पेशल" और उस आलू की आप ट्रेन ले जाइए साउथ में, वेस्टर्न इंडिया में और दूसरी जगहॉ में आप का जो नाफेड है, जो दूसरी मारकेटिंग फेडरेशंस हैं उनसे बात कीजिए उसको प्रमोट कीजिए तकि किसान अगले साल भी खून पसीना करके उपज करे तो उसको सही कीमत मिले । आज वह सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है । मैदान में आलू सड़ रहा है । उसको ब्लीचिंग पाउडर देकर दफनाया जा रहा है । यह बहुत गलत हो रहा है हमारे मुल्क के लिए । लांग टर्म इफेक्ट के लिए आप कोल्ड स्टोरेज प्रमोट कीजिए । इसके लिए कुछ फंड दीजिए, कुछ इंसेंटिव बनाइए । अभी जो आलू रखा है उसकी मारकेटिंग और खरीदारी के लिए जैसे आप ओनियन के लिए, दूसरी उपज के लिए करते हैं, उसी तरह से आलू के लिए भी कीजिए जाकि किसान को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सके । इसके लिए असिस्टेंस देना पड़ेगा ।

شری محمد سلیم پشچمی بنگال: دھنیواد مہودیہ۔ میں آپکے مادھیم سے اس سدن کا اور سرکار کا دھیان ایک اہم و شے پر آکرشت کرانے جا رہا ہوں ۔ مہودے پشچمی بنکال اور دیش کے دوسرے بھاگوں میں اس سال قضا زیادہ آلو کا چلن ہوا ہے کہ وہ آلو اتپادن کسانوں کیلئے ایک بدنصیبی کا کارن بن گیا ہے۔ اسکے پاس ا سے رکھنے کیلئے "کولڈ اسٹوریج"

†ITranslilcration in Arabic Script

جاتا ہے کہ ۱۹۵۹ کا آرڈر ہے سنٹرل گورنمنٹ کا کہ آلو میں وائرس ہوا تھا اسلئے کوئی آلو آپ و دیش میں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ جبکہ ساؤتھ میں ہمارا بنگال کا آلو جاکر وہاں سے شری لنکا تک جا رہا ہے۔ اسمگلنگ ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش میں جو اسمگلنگ ریٹ ہے آج وہ دلی میں بہت حاوی ہے۔ قانونا وہ نہیں جا سکتا ہے وائرس کی وجہ سے لیکن روزہی آپ دیکھیں سڑک کے کنارے میں بارڈر ایریاز میں ..."مداخلت"... وہ وہاں "ان آفیشیلی" جا رہا ہے۔ یہاں کرشی منتری جی موجود ہیں۔ کامرس منسٹر صاحب سے بات کریں اس آرڈر کو چینج کریں ۔ سپریم کورٹ کی اگر کوئی رائے ہے تو اسکو بدلیں۔ وہ زمانہ بدل گیا ہے۔ وہ آلو بدل گیا ہے۔ اس اسپیسی "کا آلو نہیں ہے۔ دوسرے قسم کا آلو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بدنصیبی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ وہ آرڈر ابھی بھی چل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت ایک طرف آلو خریدنا چاہتی ہے۔ امپورٹ کے لئے تیار ہے لیکن ہمارے یہاں ریسٹرکشن ہے سینٹرل گورنمنٹ کی ۔ جو کھائے گا۔جو لوگ ہیں انکو کوئی دقت نہیں ہے۔ انکو سمجھ میں آگیا ہے کہ یہ وائرس والا آلو نہیں ہے۔ لیکن ہماری دلی سرکار کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے۔ مہودیہ ۔ ہمارے دیش میں ایک طرف تو لوگ بھوک کی وجہ سے مرجاتے ہیں اور دوسری طرف جب زیادہ پیداوار ہوتی ہے تو اس بازاروں میں اور گوداموں میں رکھنے کی مناسب جگہ نہیں مل پاتی۔ میڈم ابھی پشچمی بنگال سرکار کی طرف سے کولڈ اسٹوریج سہولیت دیکر کچھ آلوں رکھا گیا ہے۔

ابھی اس آلو کے بھی باہر نکالنے کا وقت آگیا ہے اور جو نیا پھلن ہوا ہے وہ سب اس طرح سے سڑ رہا ہے۔ اسکے پیچھے کوئی کارن ہے ایک کارن تو یہ ہے میڈم کہ ۱۹۵۰ سے میرے جنم سے پہلے بنگال میں آلو کا جو "سیڈفارم" وہ "وائرس افیکٹیڈ " ہوا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے رائے دی تھی کہ بنگال کا آلو ودیش میں یا دیش کے دوسرے راجیوں میں نہیں جائیگا۔ اس کے بعد جو "بیجنباڑی سیڈ " فارم تھا ا سے بند کر دیا گیا۔ پھر یہاں نینیتال سے۔ پنت نگر سے۔ اور ہماچل سے سیڈ وہاں لے جایا گیا۔ اسکے بعد اتنے سال میں نئے طریقے سے نئے سیڈ سے زیادہ پھلن ہو ایسے آلو کی تیاری کی گئی۔ اب وہ سیڈ دوسری جگہ بھی جاتا ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں جا رہا ہے۔ آلو بھی جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش حکومت آلو خریدنا چاہتی ہے۔ ریڈی ہے۔ لیکن یہ دکھایا

یہ بہت غلط ہو رہا ہے ہمارے ملک کیلئے "لانگ ٹرم افیکٹ" کیلئے آپ کولڈ اسٹوریج پرومڈ کیجئے۔ اسکے لئے کچھ فنڈ دیجئے۔ کچھ انسینیٹو بنایئے۔ ابھی جو آلو رکھا ہے اسکی مارکیٹنگ اور خریداری کیلئے جیسے آپ "اونین" کیلئے اور دوسری فصلوں کیلئے کرتے ہیں اسی طرح سے آلو کیلئے بھی کیجئے تاکہ کسان کو "ڈسٹرس سیل" سے بچایا جا سکے۔ اسکے لئے اسسٹس دینا پڑے گا۔

उपसभापति : रिसर्च कर सकते हैं अभी उन आलुओं में कि वह वायरस है कि नहीं । There are modern methods to find out whethei these *aloos* are still virus-infected or not.

श्री सोम पाल (उत्तर प्रदेश) **:** मैडम, मैं इस संबंध में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं ।

उपसभापति : देखिए सोमपाल जी, बहुत स्पेशल मेन्शंस है । यह तो अभी उन्होंने भी बोला था मैंने ना बोला ।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : उपसभापति महोदया, यह सही है कि इस साल आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है । सिर्फ बंगाल में ही नहीं यू.पी. में भी, बिहार में भी । चारों तरफ से यह आवाज आ रही है । हमने एक महीना पहले ही वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेट्री को कहा कि हमारे पास खबर आ रही है कि आलू का डिस्ट्रेस सेल हो रहा है इसलिए आप हमको बताइए कि क्या स्थिति है । उन्होंने कहा कि कहां से रिपोर्ट आई है – तो बर्दवान से कहा । तब फिर जांच करके चीफ सेक्रेट्री ने बताया कि नहीं यहां डिस्ट्रेस सेल नहीं हो रही है । एक तो हम माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहेंगे ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार) **:** कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है ।

श्री चतुरानन मिश्र : जरा सुनिए तो । सब बातें सुन लीजिए । आप तो सुनने वाले हैं ।

میں نہیں آیا ہے کہ جو وائرس والا معاملہ تھا اس ریسٹرکشن کو ہٹا دینا چاہئے۔ دوسری طرف آج بھی دیش میں یہ صرف بنگال میں نہیں ہے۔ یو۔پی۔میں بھی کئی جگہ پر ہے کہ آلو کا کسانوں کو ۵۰ پیسہ کلو نہیں مل رہا ہے۔ اور شہروں میں آپ آیئے ابھی بھی ۳۔۴ روپیہ کلو یا ۱۰ روپئے کیلو مدراس اور بمبئی میں ہے۔ ریل منترالئے سے آپ بات کیجئے کرشی منتری جی۔ جب "ڈسٹریس سیل" ہوتی ہے اسمیں کسانوں کو بچانے کیلئے آپ کچھ نہ کچھ الگ سے دیتے ہیں کچھ انسینٹیو دیتے ہیں۔ کسطرح سے آپ کسانوں کی مدد کرینگے اس بارے میں سوچیں۔ بنگال کی حکومت سے بات کیجئے۔ بنگال کی حکومت آپ سے بات کر رہی ہے۔ضرورت پڑے تو اسپیشل ریل چلایئے "آلو اسپیشل" اور اس آلو کی آپ ٹرین لے جایئے ساؤتھ میں "ویسٹرن انڈیا" میں اور دوسری جگہوں میں۔ آپکا جو "نیفیڈ " ہے۔ جو دوسری مارکیٹنگ فیڈ ریسنس ہیں ان سے بات کیجئے اسکو پرموٹ کیجئے ۔تاکہ کسان اگلے سال بھی خون پسینہ کرکے پیدا کرے تو اسکو صحیح قیمت ملے۔ آج وہ سر پر ہاتھ رکھکر بیٹھا ہوا ہے۔ میدان میں آلو سڑ رہا ہے۔ اسکو بیلیچنگ پاؤڈر دے کر دفنایا جا رہا ہے۔

जहां तक वायरस की बात है, हमारे पास परसों, चौथे रोज यह खबर आई है । हमने अपने विभाग को दे दिया है और उन्होंने कहा है कि सेग्रीगेट कर लिया है वायरस वाले एरिया को जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर वेस्ट बंगाल से हमको खबर आई । तो उसके मुताबिक हम जल्दी से इसमें निर्णय लेंगे । हम सहमत हैं इनके विचार से । लेकिन एक बात और है जिसको कहना चाहेंगे कि नाफेड जो खरीदता है वह एम.आई.एस. स्कीम है – मारकेटिंग इन्टरवेंशन स्कीम । उसमें घाटा लगा तो आधा सेंटर और आधा राज्य सरकार देंगी । उत्तर प्रदेश ने तो कहा कि हम आधा देंगे लेकिन बंगाल, बिहार ये सब जो हमारे अपने नजदीक के हैं उन लोगों ने इस स्कीम को माना ही नहीं । वे कहते हैं टोटल आप ही खरीदिए । टोटल घाटा आप ही दीजिए **...(व्यवधान)...** सही बात है । जब दूसरे राज्यों को हम आधा देंगे तो आपको कैसे समूचा देंगे । हमने कर्नाटक में जरूर दिया है, हमने आंध्र को मिर्च में जरूर दिया है लेकिन आधा-आधा शेयर दिया है । आधा-आधा शेयर करे, हम पूरा करेंगे । हमने रेलवे मिनिस्टर से भी बात की है कि एक वैगन दिया जाए, जिसमें इन लोगों को थोड़ा कंसेशन देकर, जहां वह चाहें भेज सकें । सबसे ज्यादा खपत शायाद बांगला देश में होगी । हम उसके लिए मदद करने की बात सोच रहे हैं और बहुत जल्दी आपको सूचित करेंगे **...(व्यवधान)...**

उपसभापति : मंत्री जी, यहां आलू पर यह छाप लगी है कि वेस्ट बंगाल के आलू में वायरस है, तो उसको रिसर्च लेबोरेटरी में पहुंचवा कर और चैक करवाकर सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए तो ईजली काम हो जाएगा । खाली मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा । **...(व्यवधान)...**

श्री चतुरानन मिश्र : मैडम ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग एरिए में होता है, उसको सेगरीगेट कर दीजिए । अब यह आलू से तो पूछेंगे नहीं कि यह कहां से आए हैं **...(व्यवधान)...**

श्री सोमपाल : एक्सपोर्ट के उपर पाबंदी लगी है और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह कहा है । **...(व्यवधान)...** एक मिनट, मिश्र जी, प्लीज सुन लीजिए । It is a very limited question. There are all kinds of restrictions on the movement, marketing, value-addition and processing of agricultural products. There are so many restricitons placed on agricultural products — including potato — by the Commerce Ministry. It is a limited question. Really, a comprehensive view has to be taken. But everything you are trying to deal with in a piecemeal manner. This is a serious problem. When you were in the Opposition, you were talking about it. Now that you have become a Minister, you have started giving those evasive and vague replies. This is not the way to deal with such a serious issue.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) in the Chair]

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष जी, आप आ गए हैं चेयर पर । हमने कोई इवेसिव रेप्लाई नहीं दिया है, हमने तो क्लीयर टर्म में कहा है कि चार रोज पहले यह मामला आया। हमारे निभाग में साइंस सेक्शन है प्लान में, उस्को य दे दिया है। बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे । इसमें इवेसिव कहां है?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्द सलीम) : उन्होंने कह कि कॉमर्स मिनिस्टरी ने पाबंदी लगाई है ।

श्री चतुरानन मिश्र : आप देखिए, अभी तो हमारे ही अंडर में है। जब हम क्लीयर कर देंगे तो कॉमर्स मिनिस्टरी **...(व्यवधान)...** इसमें इवेसिव नहीं है।

श्री सोमपाल : उपसभाध्यक्ष जी, कॉटन में यही हुआ। मंत्री जी ने समिति बैठाई। हमने संस्तुति की । मैं यहां पर रेकार्ड पर कहना चाहता हूं सदन से, कि आपने समिति बैठाई थी और हमने संस्तुति की थी कि सरकार का जो निगम है, कपास निगम , काटन कारपोरेशन आफ इंडिया, उसको सिर्फ आप इजाजत दे दीजिए तीन लाख गांठ एक्सपोर्ट कर्ने की , इससे दाम बढ़ जाएगा । गिरी प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे , जो आप ही की साम्यवादी पार्टी के हैं । कुछ जगह हम गए, डिमोंस्ट्रेशन हुए। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी । प्रधानमंत्री जी से हम मिले, आपको मिले । कोई निर्णय आपने नहीं लिया और आप कहते हैं कि इवेसिव रेप्लाई नहीं है ।

श्री चतुरानन मिश्र : सुनिए, अभी आलू पर थे और अब आप कॉटन पर आ गए।**...(व्यवधान)...** अब जरा हमारी बात भी सुन लीजिए। हमको अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है कमेटी ने। आप अपनी अलग बात कहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं **...(व्यवधान)...**

SHRI SOM PAL: Mr. Vice-Chariman, he made an interim recommendation. This Committee made an interim recommendation. *(Interruptions)*

श्री चतुरानन मिश्र : आप सब बात कह दीजिए। उसके बाद आपको बाद में जवाब दे देंगे। यह बार-बार उठना, बैठना समझ में नही आता। **...(व्यवधान)..**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि समिति बन जाती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट की इंपलीमेंटेशन बात है ।

SHRI SOM PAL: The action should have been taken at the time of the harvest. If you take action now, it is not going to be of any use. It is infructuous. I am walking out in protest.

(The hon. Member then left the Chamber.)

श्री चतुरानन मिश्र :देखिए, हमारे पास रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। यही रिपोर्ट आई थी कि हम यह करेंगे तो हमने कॉमर्स मिनिस्टरी को लिखा था कि इनको इजाजत दे दी जाय एक्सपोर्ट करने की । कॉमर्स से आया था कि 13 लाख बेल का हम लोग देंगे, यही काटन के लिए ।

Re. Scarcity of drinking water in Uttarakhand area of U.P.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, जिसे अब उत्तरांचल और उत्तराखंड के नाम से जना जा रहा है, वहां पेयजल के संकट के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उस क्षेत्र का यह दुर्भाग्य कहना चाहिए कि वहां का जो मीठा जल है वह बड़ी मात्रा में प्रवाहित होकर मैदान में आता है, लेकिन यहां पेयजल की समस्या बनी हुई है । यानि जैसी कहावत है- पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसके उपयोग में नहीं आ रही है। उस क्षेत्र में अनेक बड़ी पेयजल योजनाएं बनीं, जैसे पिथौरा गढ़ की जलापूर्ति योजना है, अल्मोड़ा की जलापूर्ति योजना है , पौड़ी की जलापूर्ति योजना है। यह तो नगरीय क्षेत्र है, यहां के जिला मुख्यालय भी हैं। इसके अलावा दूसरी योजना है हिंडोलाखाल योजना, दशरथ पंपिग योजना, जो पचास-पचास, साठ-साठ ग्रामीण समूह के लिए बनी हुई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विशाल पूंजी जल की आपूर्ति के लिए उस क्षेत्र में लगाई जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है इस बार भी इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र ने 10 करोड़ रुपए अलग से उस क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए गढ़वाल मंडल को दिए हैं और 30 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने मुहैया कराया है। लेकिन स्थिति यह बन गई है कि वहां पर चारों तरफ पेयजल कि हा-हाकार हो रही है और प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती । दुर्भाग्य यह है कि वहां का जो शासन तंत्र है उसको इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती है कि वह पानी की व्यवस्था कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और यह होता है कि मैदान कि तरह जो इंडिया मार्क के हैंड पम्प यहां पर लगाए गे हैं, पहाड़ में खार खाते हैं, जिसको शिखर कह सकते हैं, उस शिखर के स्थान पर भी इंडिया मार्क के हैंड पम्प लगे हुए हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि वहां का प्रशासन उस दिशा में अचेतन है और यही कारण है कि पूरे क्षेत्र में हा-हाकर मच गया है, सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करती है तो प्रशासन यह करता है कि जब पानी घट जाता है तो नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पानी दिया जाता है लेकिन जो ग्रमीण क्षेत्र हैं, उसकी चिंता नहीं की जाती है और दिखाने के लिए लगभग जून के बाद कहीं-कहीं खच्चरों से पानी भेजा जाता है । आप सब अनुभव कर सकते हैं कि खच्चरों से पेयजल की कैसी आपूर्ति होगी । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो जल का संकट है, यह एक प्रकार का कृतिम संकट है और इसके लिए शासन में बैठे हुए लोग बड़ी मात्रा में जिम्मेदार है क्योंकि जो फंड दिया जाता है वह बड़ी मात्रा में दूसरे रास्तों से दूसरी तरफ चला जाता है और उससे कोई परिणाम नहीं आता है । मैं यह भी चाहता हूं कि ठीक समय पर, जैसे अभी पानी की कमी शुरू हो रही है । उसकी व्यवस्था शासन अभी से कराए और उसकी मॉनिटरिंग,देख-रेख की व्यवस्था भी कराए ।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

Re. Enactment of Legislation for Agricultural Workers

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा (बिहार)**:** महोदय, फिर एक बार मैं सरकार की उस प्रतिबद्धता की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो खेत मजदूरों के बारे में केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में हैं ।

महोदय, इस बारे में बहुत बार यहां बहस हो चुकी है और सरकार की तरफ से श्रम मंत्री ने दो-दो बार इस सदन में अपने कमिट्मेंट को दोहराया कि शीघ्र ही यह कानून बनाया जाएगा । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट इस बारे में